में पहले चरण में 14 सड़कों के निर्माण तथा दूसरे चरण में 61 सड़कों के निर्माण के अनुमान शामिल किए गए थे। इनमें से, राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के अनुसार 14 सड़कों, जिनमें दूसरे चरण की एक सड़क भी शामिल है, को 1985-86 तथा 1986-87 में अनुमोदित कर दिया गया था। सभी निर्माण कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश सरकार से 10 अन्य सड़कों के निर्माण के लिये भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पहले से स्वीकृत कार्यों की असंतोषजनक प्रगति तथा राज्य सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की वजह से 10 सड़कों के लिये प्रशासनिक अनुमोदन नहीं दिया जा सका। इस योजना को 1992-93 में राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

Socio Economic Development in Arunachal Pradesh

84042-G SHRI NYODEK YONG-GAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Rural Works Department (RWD) of Arunachal Pradesh have helped achieving Socio-economic development of the people of Arunachal Pradesh; and

(b) if so, the details thereof with effect from 1989 onwards.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) During the last two years i.e. 1989-90 and 1990-91, various developmental activities were taken up by the Rural Works Department (RWD) for uplift-ment of Socio Economic conditions of the poor people of Arunachal Pradesh. Some of the achievement made during this period were; (i) more than 5500 hectares of land added for assured irrigation (ii) 260 villages fully covered and 44 villages partially covered under Rural Water Supply Programme, (iii) 95 Filtration Plants for water supply purposes installed, (iv) 141 Kms. fair weather roads constructed alongwith 24 suspension bridges, 49 culverts under rural link road programme. In the soil sector, more than 4500 heetars of land protected and about 700 hectares of land developed for cultivation. 20 Bio-Gas Plants installed. About 2700 improved chulhas distri buted and installation of 106 solar P. V. street lights done.

Previously Unstarred Question 4320, transfeirrad from the 27th March, 1992.

जल-परीक्षण प्रयोगशालाओं का स्थापित किया जाना

\$\$4042—ज. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में प्रत्येक जिले में एक जल-परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जल की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विगत में चलती फिरती प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की अनुमति दी थी और क्या ऐसी प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर ऐसी प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1989—90 से 1991—92 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 110 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए पहले ही अनुमोदन दे दिया है। आठवीं योजना में नीति और परिव्ययों, जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है, के आधार पर सरकार का प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक जल-जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का है।

\$\$Previously Unstarred Question 4331, transfered from the 27th March, 1992 1992.